(c) The growth rates in 1990's were significantly lower in agriculture sector and marginally lower in industry sector as compared to corresponding rates in 1980's. Services sector grew somewhat faster in 1990's than in 1980's. On the whole, the GDP in 1990's grew at a slower rate than in 1980's. Figures are given in annexed statement.

Statement

Growth rates of gross domestic product (GDP) at constant (1980-81) prices during the period 1991-92 to 1996-97

(Per Cent)

Sector	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96[3]	1996-97[4]	Average 1991—97	Average 1980—90
Agriculture[1]	−2.3	6.1	3.6	4.6	−0.1	5.7	2.9	4.5
Industry[2]	−1.3	4.2	6.8	9.4	11.6	7.0	6.3	6.9
Services	4.9	5.5	7.3	7.5	8.8	7.4	6.9	6.4
Total GDP	**0.8**	**5.3**	**6.0**	**7.2**	**7.1**	**6.8**	**5.5**	**5.9**

Note: 1. Agriculture including livestock, forestry and logging and fishing.
2. Industry includes mining, manufacturing, electricity and construction.
3. Quick Estimates.
4. Revised Estimates (First update of advance estimate).

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए लक्ष्य

274. **श्री अजीत जोगी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पिछले दो वर्षों के दौरान गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लागू किए जाने का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में इन कार्यक्रमों के लागू किए जाने की देख-रेख हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इन लक्ष्यों को जल्दी से जल्दी प्राप्त करने हेतु राज्य-वार क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला देहरेश्वर सवनूर): (क) से (ग) देश में कार्यान्वित किये जा रहे ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के बड़े केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम हैं एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी), जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई), रोजगार आश्वासन स्कीम (ई ए एस)।

पिछले दो वर्षों आर्थात् 1995-96 और 1996-97 में इन कार्यक्रमों के अंतर्गत लक्ष्यों एवं उपलब्धियों के संदर्भ में राज्यवार वास्तविक निष्पादन को अनुपत्र में दिया गया है। [देखिए परिशिष्ट 181, अनुपत्र संख्या 10]

सरकार इन बड़े ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की नियमित मानिटरिंग केन्द्र स्तरीय समन्वय समिति, राज्य स्तरीय समन्वय समिति और जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डी आर डी ए) के शासी निकाय द्वारा जिला स्तर पर करती है। इन कार्यक्रमों की मानिटरिंग "की इंडीकेटर्स" पर राज्यों से प्राप्त नियमित प्रगति रिपोर्टों और केन्द्र, राज्य एवं कार्यान्वयक एजेंसियों के अधिकारियों द्वारा फील्ड निरीक्षणों के गहन तंत्र के माध्यम से भी की जाती है। इन स्कीमों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की पुनरीक्षा के लिए ग्रामीण विकास के राज्य सचिवालय इंचार्ज के साथ समय-समय पर पुनरीक्षा बैठकें और डी आर डी ए के परियोजना निदेशकों के साथ सम्मेलनों का आयोजन भी किया जाता है। राज्य, जिला और ब्लाक स्तरों में मानिटरिंग एवं सतर्कता समितियां भी गठित की गई हैं जिनमें इन स्कीमों के कार्यान्वयन की मानिटरिंग के लिये लोगों के चुने गये प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है।

इसके अलावा आई आर डी पी एवं जे आर वाई जैसे विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के सम्पूर्ण प्रभाव का उनके विशिष्ट उद्देश्यों के संबंध में मूल्यांकन करने के

लिये ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र मान्यता प्राप्त संस्थाओं/संगठनों के माध्यम से इन स्कीमों के समय-समय पर सहवर्ती मूल्यांकन किये जाते है।

Review of State Plans

275. DR. MANMOHAN SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have reviewed the State-wise progress of State Plans during the Eighth Five Year Plan period;

(b) how does performance of resource mobilisation by the States compare with the Plan targets; and

(c) whether there has been a shortfall; if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRIMATI RATNAMALA DEHARESHWAR SAVANOOR): (a) to (c) Yes, Sir. The State-wise progress of State Plans is reviewed in the Annual Plan discussions at various levels, including at the level of Dy. Chairman and Chief Ministers/Governors. The State-wise performance of resource mobilisation as against the projected resources for the Eighth Fvie Year Plan is given in the enclosed Statement *(See below)*. Though the nature and extent of shortfall in resource mobilisation varies from State to State, analysis has revealed that the shortfalls have been mainly in the balance from the current revenues, net contributions of State public enterprises and in the utilisation of external assistance.

Statement

Performance of States in Mobilisation of Resources during the Eighth Plan

(Rs. crore at 1991-92 prices)

States	Projected Resources	Anticipated Resources
(A) Non Special Category States		
Andhra Pradesh	10500	10371
Bihar	13000	5111
Goa	761	677
Gujarat	11500	9654
Haryana	5700	3762
Karnataka	12300	11155
Kerala	5460	6052
Madhya Pradesh	11100	8891
Maharashtra	18520	20608
Orissa	10000	4944
Punjab	6570	4234
Rajasthan	11500	8636
Tamilnadu	10200	11203
Uttar Pradesh	21000	14604
West Bengal	9760	6390
Total (A)	157871	126291